

वर्ष 2025 तक पेट्रोल में मिश्रण को चाहिए

1016 करोड़ लीटर एथेनॉल

कानपुर (एसएनबी)। राष्ट्रीय शर्करा संस्थान व साउथ इंडियन शुगरकेन एवं शुगर टेक्नोलॉजिस्ट एसोसिएशन के संयुक्त तत्वावधान में मंगलवार को आयोजित वेबिनार में संयुक्त सचिव (शर्करा व प्रशसन) भारत सरकार, सुबोध कुमार सिंह ने कहा कि पेट्रोल में 20 प्रतिशत एथेनॉल मिश्रण के लिए निर्धारित लक्ष्य के हिसाब से वर्ष 2025 तक 1016 करोड़ लीटर एथेनॉल चाहिए। इसके अलावा 334 करोड़ लीटर एथेनॉल अन्य उपयोगों के लिए चाहिए होगा। इसे करना इसलिए भी जरूरी है कि हमें पेट्रोल के अभाव पर भारी खर्च करना पड़ रहा है। वर्ष 2020-21 में भारत सरकार द्वारा 551 बिलियन डॉलर (विदेशी मुद्रा) खर्च कर 185 मिलियन टन पेट्रोलियम पदार्थ आयात किया गया। एथेनॉल उत्पादन उक्त विदेशी मुद्रा खर्च में बचत कर सकता है।

स्टैंडर्डिजेशन आफ एथेनॉल प्लान्ट कैपिसिटीज एंड माडल आफ शुगर डाइवर्जन विषयक वेबिनार में उन्होंने कहा कि सरकार



एथेनॉल में आयोजित वेबिनार में शामिल जला।

राष्ट्रीय शर्करा संस्थान के वेबिनार में बोले संयुक्त सचिव

वर्ष 2020-21 में 551 बिलियन डॉलर (विदेशी मुद्रा) खर्च कर आयात किया गया 185 मिलियन टन पेट्रोलियम

एथेनॉल उत्पादन इकाईयों की स्थापनाओं को प्रोत्साहित कर रही है। वर्तमान में भारत में मौजूद एथेनॉल उत्पादन क्षमता 426 करोड़ लीटर है। इनमें से 258 करोड़ लीटर अनाज आधारित आसवनियों से तथा शेष शीरा आधारित आसवनियों में बनते हैं। आगामी दो वर्षों में एथेनॉल उत्पादन बढ़ाकर 760 व 740 करोड़ लीटर करना प्रस्तावित है।

शर्करा संस्थान के निदेशक प्रो. नरेन्द्र मोहन ने गन्ने पर आधारित कच्चे माल से एथेनॉल उत्पादन के लिए विभिन्न व्यावसायिक मॉडल प्रस्तुत किये। अनाज आधारित एथेनॉल पर भी जोर दिया। टेक्नोलॉजिस्ट एसोसिएशन के उपाध्यक्ष चिन्मय ने कहा कि एथेनॉल उत्पादन से चौरफा विकास होगा। विदेशी मुद्रा की बचत होगी। मेक इन इंडिया के तहत नई इकाईयों की स्थापनाओं से रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। उद्योग, किसान व श्रमिक

सभी लाभान्वित होंगे। वेबिनार एम्बेलेड इंटरस्ट्रीज के एमडी संजय देसाई व कोर्पोरेट इंजीनियरिंग एंड प्रोजेक्ट्स प्रा.लि. के एमडी सदीप चिचंबकर ने संबंधित मशीनरियों के बारे में चर्चा की।

2025 तक पेट्रोल में 20 प्रतिशत इथेनॉल की ब्लैडिंग का लक्ष्य

कानपुर, 15 जून। राष्ट्रीय शर्करा संस्थान कानपुर और साउथ इंडियन शुगरकेन एवं शुगर टेक्नोलॉजिस्ट एसोसिएशन के संयुक्त तत्वावधान में स्टैंडर्डिजेशन आफ इथेनॉल प्लांट कैपिसिटीज एंड माडल आफ शुगर डाइवर्जन विषय पर एक वेबिनार का आयोजन किया गया। वेबिनार का उद्घाटन करते हुए संयुक्त सचिव सुबोध कुमार सिंह ने कहा कि वर्ष 2020-21 में भारत सरकार द्वारा 551 बिलियन डॉलर (विदेशी) मुद्रा खर्च करके 185 मिलियन टन पेट्रोलियम का आयात किया गया। सड़क परिवहन क्षेत्र में ईंधन की आवश्यकता 98 प्रतिशत वर्तमान में जीवाश्म ईंधन से पूरा होता है और शेष जैविक ईंधन से किया जाता है। एक सफल ई-20 कार्यक्रम देश को पर्याप्त मात्रा में ईंधन द्वारा विदेशी मुद्रा बचा सकता है। 2025 तक पेट्रोल में 20 प्रतिशत इथेनॉल की ब्लैडिंग के बड़े लक्ष्य को हम प्राप्त करने में सफल हो जायेंगे। वर्तमान में देश में



निदेशक प्रो. नरेन्द्र मोहन व अन्य।

इथेनॉल की उत्पादन क्षमता 426 करोड़ लीटर है। आगामी दो वर्षों में उत्पादन को बढ़ाकर क्रमशः 760 करोड़ लीटर और 740 करोड़ लीटर करना प्रस्तावित है। वर्ष 2025 तक 1016 करोड़ लीटर इथेनॉल, पेट्रोल में मिश्रण के लिए तथा 334 करोड़ लीटर अन्य उपयोगों के लिए उपलब्ध होगी।

संस्थान के निदेशक प्रो. नरेन्द्र मोहन ने कहा कि गन्ने पर आधारित कच्चे माल से इथेनॉल उत्पादन के लिए विभिन्न व्यावसायिक मॉडल प्रस्तुत किये। यदा सी एवं बी हैवी सीरी, गन्ने का रस, शर्करा, शर्करा की चाशनी और चावल, मक्का और अन्य फीड स्टॉक के माध्यम से भी इथेनॉल उत्पादन पर प्रकाश डाला।

'20 pc ethanol blending in petrol by 2025'

PNS ■ KANPUR

Subodh Kumar Singh, Joint Secretary (Sugar & Administration), while inaugurating a webinar on 'Standardisation of Ethanol Plant Capacities and Models of Sugar Diversion' on Tuesday, at the National Sugar Institute here, said that India's net import of petroleum was 185 MT at a cost of USD 551 billion in 2020-21.

He said keeping in view the fact that about 98 per cent of the fuel requirement in the road transportation sector was currently met by fossil fuels and the remaining 2 per cent by biofuels, a successful E20 programme could save the country a substantial amount of revenue.

He said the country was in pursuit of achieving 20 per cent blending of ethanol in petrol by 2025 and thus many policy interventions had been made for expediting the setting up of ethanol units.

He said the current ethanol production capacity in India was of 426 crore litre derived from molasses-based distilleries and 258 crore litre from grain based distilleries and was proposed to be expanded to 760 crore litre and 740 crore litre respectively in the next years.

He said this would be sufficient to produce 1,016 crore litre ethanol required for ethanol blending in petrol and 334 crore litre for other uses by 2025.

NSI Director and organis-

er of the webinar, Prof Narendra Mohan, emphasised upon standardising the capacities and configuration of plant and machinery to higher productivity, lower cost of production, reducing the project cost and project completion time.

He presented various business models for producing ethanol from sugarcane-based raw materials like C&B heavy molasses, sugarcane juice, sugar, sugar syrup and also from rice, maize and through other feed stocks.

He said already there was an all time high blending of over 7.5 per cent during the current ethanol supply year and expected to achieve 8.0 per cent as a whole for the year.

He added that one had to look for round the year operations of ethanol plants using multiple feed stocks as per availability and economics.

Chinnapan N, vice-president of South Indian Sugarcane and Sugar Technologists Association, in his address said that biofuels like ethanol besides saving foreign exchange and economic sustainability to sugar industry could also help to generate employment, promote Make in India, Swachh Bharat, doubling of farmers' incomes and converting waste to wealth.

Sanjay Desai, managing director of Excel Industries, made a presentation on selection of plant and machinery to make ethanol units workable on different feed stocks.

He said initially, such a unit may cost more, maybe by 25-35 per cent, but then one was sure of operating it on cane juice, syrup, molasses or grains, thus, providing greater flexibility.

Sandeep Chichbankar, managing director, Of Covalent Engineering & Projects Pvt. Ltd., discussed details of various factors to be considered while selecting plant and machinery for reducing project cost and workability of various feed stocks without compromising on efficiency.

The joint organiser was the South Indian Sugarcane and Sugar Technologists Association and a large number of delegates from various sugar producing states participated in the webinar.

गन्ने के शीरे से बनाएंगे 334 करोड़ लीटर एथेनॉल

कानपुर। केंद्र सरकार ने पेट्रोल में मिलाने के लिए डिस्टिल्टरी (आसवनियों) से दो साल में गन्ने के शीरे से 334 करोड़ लीटर एथेनॉल और अनाज अवशेष से 482 करोड़ लीटर एथेनॉल बनाने का लक्ष्य रखा है। इससे वर्ष 2025 तक 20 प्रतिशत एथेनॉल पेट्रोल में मिलाया जा सकेगा। इस संबंध में मंगलवार को नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट (एनएसआई) और साउथ इंडियन शुगरकेन एंड शुगर टेक्नोलॉजिस्ट एसोसिएशन के बैनर तले आयोजित वेबिनार में मंथन किया गया।

वेबिनार का उद्घाटन केंद्रीय संयुक्त सचिव शर्करा एवं प्रशासन सुबोध कुमार सिंह ने किया। उन्होंने बताया कि वर्तमान में सड़क परिवहन क्षेत्र में ईंधन की 98 प्रतिशत जरूरत जीवाश्म ईंधन से और बाकी दो प्रतिशत जरूरत को जैव ईंधन से पूरा किया जाता है।

पेट्रोल में एथेनॉल मिश्रण से आयात कम करके विदेशी मुद्रा के खर्च को कम किया जा सकता है। नई एथेनॉल इकाइयों की स्थापना के लिए सरकार नीतिगत प्रयास कर रही है। वर्तमान में शीरा आधारित आसवनियों से 426 करोड़ लीटर उत्पादन होता है, इसे बढ़ाकर 760 करोड़ लीटर किया जाना है। अनाज आधारित आसवनियों से 258 करोड़ लीटर उत्पादन होता है, इसे दो साल में बढ़ाकर 740 करोड़ लीटर किया जाना है। इस मौके पर एनएसआई के निदेशक प्रोफेसर नरेंद्र मोहन ने मशीनरी क्षमता, मानकीकरण, उत्पादन एवं परियोजना लागत कम करने और समय से पूरा करने पर बल दिया। वेबिनार में विभिन्न संस्थानों ने मॉडल भी प्रस्तुत किए। (ब्यूरो)

वेबिनार में केंद्रीय संयुक्त सचिव ने दी जानकारी

वर्ष 2025 तक पेट्रोल में मिलाया जा सकेगा 20 प्रतिशत एथेनॉल

राष्ट्रीय शर्करा संस्थान, कानपुर और साउथ इंडियन शुगरकेन एवं शुगर टेक्नोलॉजिस्ट्स



4 साल बाद 20 परसेंट एथेनॉल पेट्रोलियम प्रोडक्ट में मिलाएंगे

ब्रिटीशएनए

कानपुर। ऑन लाइन वेबीनार का उद्घाटन करते हुए सुबोध कुमार सिंह, संयुक्त सचिव (शर्करा और प्रशासन), भारत सरकार ने बताया कि वर्ष 2020-21 में भारत सरकार द्वारा 551 बिलियन डॉलर (विदेशी मुद्रा) खर्च करके 185 मिलियन टन पेट्रोलियम का आयात किया गया। उन्होंने कहा कि इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि सड़क परिवहन क्षेत्र में ईंधन की आवश्यकता का लगभग 98% वर्तमान में जीवाश्म ईंधन से पूरा होता है और शेष केवल 2% जैव ईंधन द्वारा पूरा किया जाता है, इस दिशा में एक सफल 420 कार्यक्रम देश को पर्याप्त मात्रा में ईंधन के उत्पादन द्वारा विदेशी मुद्रा के खर्च से बचा सकता है। श्री सिंह ने आगे कहा कि वर्ष 2025 तक पेट्रोल में 20 प्रतिशत इथेनॉल की ब्लेंडिंग के बड़े लक्ष्य को हम प्राप्त करने में सफल हो जाएंगे। इस दिशा में लक्ष्य प्राप्त हेतु नई इथेनॉल इकाइयों की स्थापना की दिशा में सरकार द्वारा कई नीतिगत प्रयास किये जा रहे हैं। वर्तमान में भारत में मीजूदा इथेनॉल उत्पादन क्षमता 426 करोड़ लीटर है जिसका उत्पादन शीरा आधारित आसवनियों से होता है। 258 करोड़ लीटर उत्पादन अनाज पर आधारित आसवनियों से है। आगामी दो वर्षों में इस उत्पादन को बढ़ाकर क्रमशः 760 करोड़ लीटर और 740 करोड़ लीटर करना प्रस्तावित है। इससे वर्ष 2025 तक 1016 करोड़ लीटर एथेनॉल, पेट्रोल में मिश्रण के लिए तथा 334 करोड़ लीटर अन्य उपयोगों के लिए उपलब्ध होगी।

गन्ना बेहतर कच्चे रा मटेरियल से एथेनॉल बनाए

राष्ट्रीय शर्करा संस्थान, कानपुर के निदेशक, नरेंद्र मोहन, ने अपने संबोधन में संयंत्र और मशीनरी की क्षमता एवं प्रकार के मान्यीकरण, उत्पादन एवं परियोजना लागत को कम करने तथा परियोजना के कम समय में पूरा करने पर विशेष जोर दिया। उन्होंने गन्ने पर आधारित कच्चे माल से इथेनॉल उत्पादन के लिए विभिन्न व्यावसायिक मॉडल प्रस्तुत किए यदा च्सीच एवं च्सीच हेवी सीरे, गन्ने का रस / शर्करा /

शर्करा की दाशनी और धावल, मक्का और अन्य फीड स्टॉक के माध्यम से भी इथेनॉल उत्पादन पर प्रकाश डाला। उन्होंने ने कहा कि वर्तमान इथेनॉल आपूर्ति वर्ष के दौरान हमने सर्वकालिक उच्च ब्लेंडिंग प्रतिशत 7.5 से अधिक पहले ही प्राप्त कर लिया है और इसे पूरे वर्ष के लिए समग्र रूप से 8.0 प्रतिशत प्राप्त करने की आशा रखते हैं। हालांकि, हमें उपलब्धता और अर्थशास्त्र के अनुसार विविध फीड स्टॉक्स का उपयोग करते इथेनॉल संयंत्रों को पूरे वर्ष के संचालन हेतु प्रयास करना होगा।

वेस्ट से किसानों की आय दोगुनी कर सकते हैं

श्री चित्रापन, उपाध्यक्ष, साउथ इंडियन शुगरकेन एवं शुगर टेक्नोलॉजिस्ट्स एसोसिएशन ने अपने संबोधन में कहा कि जैव ईंधन जैसे इथेनॉल का उत्पादन विदेशी मुद्रा की बचत और चीनी उद्योग को आर्थिक स्थिरता प्रदान करने के साथ-साथ भारत में नुवाओं हेतु रोजगार पैदा करने, मेक इन इंडिया, स्वच्छ भारत को बढ़ावा देने, किसानों की आय को दोगुना करने, कूड़े-कचरे से धनोपार्जन में भी मदद करता है।

प्लांट लगाने में 25 से 35% लागत अधिक हो सकती है

इस महत्वपूर्ण वेबीनार के दौरान श्री संजय देसाई, प्रबंध निदेशक, मे. एक्सेल इंडस्ट्रीज ने विभिन्न फीड स्टॉक से इथेनॉल इकाई को चलाने के लिए संयंत्र और मशीनरी के बचन पर प्रस्तुति दी। श्री देसाई ने कहा कि प्रारंभ में ऐसी इकाई की स्थापना लागत 25-35% तक अधिक हो सकती है, लेकिन तदुपरांत विविध फीड स्टॉक जैसे गन्ने के रस, सिरप, शीरा या खाद्य पदार्थों से इथेनॉल का उत्पादन करके अतिरिक्त आय प्राप्त की जा सकती है। संदीप चिचंबरकर, प्रबंध निदेशक, मे. कोर्पोरेट इंजीनियरिंग एवं प्रोजेक्ट्स प्रा. लिमिटेड ने दक्षता से समझौता किए बिना विभिन्न फीड स्टॉक से इथेनॉल निर्माण हेतु संयंत्र और मशीनरी का बचन करते समय परियोजना लागत को कम करने के विभिन्न कारकों के विवरण पर विस्तृत चर्चा की।

नई इकाइयों से पेट्रोल में होगी 20 फीसद एथनॉल की ब्लेंडिंग

जासं, कानपुर : राष्ट्रीय शर्करा संस्थान, साउथ इंडियन शुगरकेन एवं शुगर टेक्नोलॉजिस्ट्स एसोसिएशन की ओर से मंगलवार को स्टैंडराइजेशन ऑफ इथेनॉल प्लांट कैपिसिटीज एंड मॉडल्स ऑफ शुगर डिवीजन विषय पर वेबिनार हुआ। शर्करा और प्रशासन के संयुक्त सचिव सुबोध कुमार सिंह ने कहा कि पेट्रोल में 20 फीसद एथनॉल की ब्लेंडिंग के लिए नई इथेनॉल इकाइयां खोली जा रही हैं। सड़क परिवहन क्षेत्र में ईंधन की

आवश्यकता का करीब 98 फीसद जीवाश्म ईंधन से पूरा होता है, जबकि महज दो फीसद जैव ईंधन से मिलता है। वर्तमान समय में इथेनॉल उत्पादन की क्षमता 426 करोड़ लीटर है। यह शीरा आधारित डिस्टिलरी से मिलता है। 258 करोड़ लीटर का उत्पादन अनाज पर आधारित डिस्टिलरी से होता है। एनएसआइ के निदेशक प्रो. नरेंद्र मोहन ने गन्ने पर आधारित कच्चे माल से एथनॉल उत्पादन के लिए व्यवसायिक मॉडल प्रस्तुत किए।